



- केंद्र ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।
- लोकसभा में कल औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के संबंध में संशोधन विधेयक पेश किया गया।
- द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने उप-राज्यपाल से बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की।
- पशुपालन विभाग ने केंद्रीय योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत द्वीपसमूह में पहली उन्नत प्रजनन तकनीक को लागू किया।



सरकार ने भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के गायन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाएं, तो राष्ट्रीय गीत के सभी पहले छह छंद गाना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे प्रमुख राजकीय अवसरों पर पूरे छह छंद वाला राष्ट्रीय गीत गाया जाना अनिवार्य होगा। नागरिक अलंकरण समारोहों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर, राजकीय समारोहों और सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण बजाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आकाशवाणी और टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और बाद में तथा राष्ट्रीय ध्वज को परेड में ले जाने के समय भी राष्ट्रगान बजाया जाना अनिवार्य होगा।



औद्योगिक संबंध संहिता 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कुछ कानूनों की निरंतरता को लेकर भविष्य में किसी भी अनावश्यक जटिलताओं से बचने के उद्देश्य से एक संशोधन विधेयक कल लोकसभा में पेश किया गया। औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शून्यकाल के दौरान पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को प्रतिस्थापित करता है, जो ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक रोजगार और औद्योगिक विवादों से संबंधित हैं।



लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 2025 बैच के 30 आईएस प्रशिक्षुओं के एक समूह ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी से शिष्टाचार भेंट की। यह दल अपने 'विंटर स्टडी टूर' के तहत द्वीप समूह के दौरे पर है।



दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के मानसिक तनाव और मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए दक्षिण अंडमान अंचल में समिति का गठन किया गया है। इस समिति में स्थानीय अधिकारियों और स्रोत अधिकारियों को शामिल किया गया है। विद्यार्थी जी बी पंत अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आनन्द लिंगेश्वरन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निधि प्रकाश, श्यामली सिंह, सीनियर सेकेण्डरी स्कूल कैम्पबेल बे उप-प्रधानाचार्या बिन्दु वर्मा, पीएम श्री सीनियर सेकेण्डरी स्कूल प्रातरापुर के उप-प्रधानाचार्य पंकजाशन नायर और पीएम श्री सीनियर सेकेण्डरी स्कूल रंगत के उप-प्रधानाचार्य डॉ. सुशीम कुमार बिश्वास से संपर्क कर सकते हैं।



राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 'सी-डैक' के सहयोग से ISEA परियोजना के तहत पूरे द्वीप समूह में जागरूकता सत्रों की एक श्रृंखला आयोजित की। इस वर्ष का वैश्विक विषय स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्प – एआई का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग था। इन सत्रों का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं, साइबर स्वच्छता, डिजिटल खतरों से सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना था। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित सत्र में कॉलेज विद्यार्थियों, आईटी कैंडर के अधिकारियों और एनआईसी टीम ने भाग लिया। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्या मंजु लता राव और एनआईसी के एसआईओ ने सुरक्षित इंटरनेट एक्सेस, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और डिजिटल सुरक्षा उपायों पर प्रस्तुति दी। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर और कार निकोबार जिला कार्यालय में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए।



द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान' के नाम से डीम्ड यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रशासन के निर्णय पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। इस संबंध में उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में सांसद ने बताया कि इस निर्णय के विरोध में छात्र समुदाय और विभिन्न हितधारकों ने कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया है। सांसद ने प्रधानमंत्री से भी इस निर्णय की समीक्षा करने और केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन है। सांसद ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी स्थापित करने की प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि भारत सरकार सांसद के आवेदन पर अंतिम निर्णय न ले ले। उन्होंने द्वीपों में शांति बहाली और उच्च शिक्षा के भविष्य के लिए निष्पक्ष निर्णय हेतु तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है।



द्वीपसमूह में डेयरी विकास की दिशा में कदम उठाते हुए पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने ईईटी- भ्रूण स्थानांतरण तकनीक परियोजना की शुरुआत की है। पशुपालन विभाग ने केंद्रीय योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उन्नत प्रजनन तकनीक को पहली बार द्वीपसमूह में लागू किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय मवेशियों की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना और दूध उत्पादन को बढ़ाना है। विभाग की सचिव पल्लवी सरकार ने सरकारी पशु फार्म, डॉलीगंज में इस प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस योजना के तहत शुरुआती चरण में दक्षिण अंडमान के चुनिंदा समूहों पर ध्यान दिया जाएगा। जानवरों का चयन उनकी प्रजनन क्षमता के आधार पर होगा। चयनित पशु मालिकों को विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे। आने वाले समय में इस परियोजना को अन्य द्वीपों और प्रमुख दूध उत्पादक क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सभी इच्छुक पशु मालिकों से अपने नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क करने को कहा गया है।



ब्रिचगंज स्थित बफल रेंज में आज छोटे हथियारों से फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर एक बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा। यह अभ्यास कल सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर एक बजे तक भी जारी रहेगा। इस संबंध में सभी संबंधितों से निर्धारित समय के दौरान स्वयं को, अपने वाहनों और पशुधन को फायरिंग रेंज से दूर रखने को कहा गया है।



पंचायती राज संस्थान के सदस्यों और आम जनता के लिए कल क्षय रोग जागरूकता-सह-स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टीबी के लक्षणों, निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र अभियान पर एक स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला क्षय रोग केंद्र की चिकित्सा अधिकारी डॉ. एलिस बा ने टीबी के कारणों, रोकथाम, उपचार और समय पर निदान के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कुल 35 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले, चिकित्सा अधिकारी ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम टीम के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लॉन्ग आइलैंड का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य टीबी नियंत्रण गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण करना था।



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय, श्री विजयपुरम द्वारा डिगलीपुर में आयोजित तीन दिवसीय 'पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी-सह-व्यापार मेला' का कल समापन हो गया। समापन अवसर पर उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना, उद्योग विस्तार अधिकारी आफरीन निशा, और एमएसएमई के सहायक निदेशक जी.के. सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और युवाओं में MSME क्षेत्र, पीएम विश्वकर्मा योजना और हरित ऊर्जा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मेले में कुल 57 स्टॉल लगाए गए थे, जहां स्थानीय शिल्प और उत्पादों का प्रदर्शन व विपणन किया गया। इस आयोजन से स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को अपने कौशल दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।

